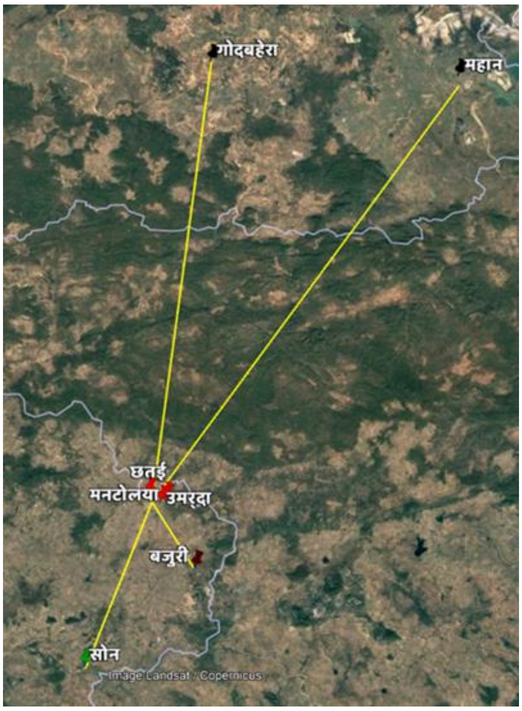
विद्युत ताप गृह (थर्मल पावर प्लांट) का प्रकृति पर असर

किसी भी इलाक़े में कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनने लगता है तो स्थानीय लोग घबरा जाते हैं. कुछ की उम्मीद बनती है कि विकास होगा, पक्की नौकरी लग जाएगी. लेकिन ज़्यादातर जनता सोचती है, ज़मीन चली जाएगी, कहीं जीना और मुश्किल तो नहीं हो जायेगा? असमंजस में फंसे लोग किसी उस्ताद को ढूँढ़ते हैं जो दूध का दूध, पानी का पानी बता दे. क्या लोग खुद से नहीं समझ सकते?

यह कहानी पूर्वी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला, कोतमा तहसील में बनने वाली ताप विद्युत् गृह (TPP) का है.



चित्र 1 - ATEPL का कोयला और पानी



चित्र 2 - ATEPL की ज़मीन

चित्र 1 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर तीन गाँवों के दिखाया गया है - छतई, उमर्दा और मनटोलिया - जिनकी ज़मीन पर ATEPL नामक TPP बनेगा. जिसमे कोयले को जला कर पानी से भाप पैदा करेंगे. उस भाप के दबाव से टरबाइन घूमेगी और बिजली पैदा होगी. कोयला आएगा उत्तर में गोदबहेरा और महान के खदानों से. रेलगाड़ी दक्षिण में बिजुरी स्टेशन तक आएगी. पानी दक्षिण में सोन नदी और केवई नदी के संगम से आएगी.

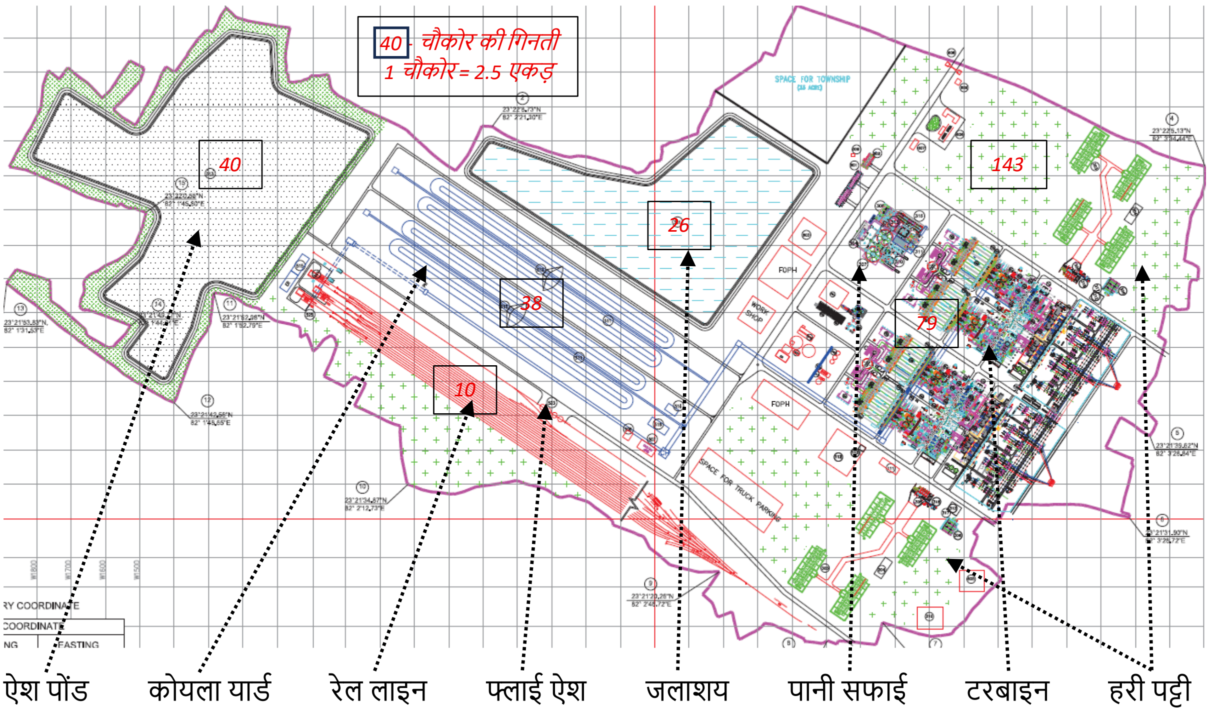
चित्र 2 में ATEPL के लिए तय ज़मीन दर्शाई गई है. केवई नदी इस ज़मीन को तीन तरफ से घेरे हुए है. परन्तु केवई, जो सोन नदी की शाखा है, में इतना पानी नहीं कि TPP की ज़रूरत को पूरा कर सके. इन चित्रों के आधार पर हम उन सवालों को पूछ सकते हैं जिससे TPP के पर्यावरणीय असर का अंदाज़ा लगाया जा सके. इसी को EIA कहते हैं, जो तैयार नहीं हुई है. लेकिन प्रोजेक्ट के प्रारंभिक रिपोर्ट (DPR) का सहारा लेकर EIA के खाका को समझने की कोशिश कर सकते हैं.

<u>पहले देखते हैं उन चीज़ों को जो ATEPL के **अंदर** जाएँगी</u>:

पूँजी – रु.36,600 करोड़ चाहिए प्लांट को बनाने के लिए. इतने पैसों को खर्च करने की ज़रूरत के लिए DPR में दो बातें कहीं जा रही हैं. पहली बात, कि विदेश को दिखाना है कि हम पूँजी के कितने बड़े दोस्त हैं. तभी विदेशी धनवान अपना पैसा देश में डालेंगे. दूसरी बात, कि उससे देश को कितना विकास होगा. छुपी हुई बात तो यह है

कि इस समय TPP में पैसा डालने का मतलब है लगभग 20 फीसदी मुनाफा. EIA को इस राज़ को खोल कर बताना चाहिए कि देश की जनता को असल में कितना हिस्सा मिलेगा?

ज़मीन – तीन गांव के कुल ज़मीन का एक-तिहाई हिस्सा (917 एकड़) पर ATEPL का कब्ज़ा होगा. जिसमे से 84 फीसदी किसानों की है. प्लांट के लिए मात्र एक-चौथाई इस्तेमाल होगा, एक-तिहाई हरी पट्टी के लिए, और बाकि कोयला पानी राख जमा करने के लिए (**चित्र 3** में चौकोर को गिन कर अंदाज़ लगाया जा सकता है). EIA में बताना चाहिए कि, दूसरे क्षेत्रों के मुक़ाबले, इन गाँवों को ही क्यों चुना गया? पास में न कोयला, न पानी, न रेल. क्या इसलिए कि यहाँ के अनपढ़ आदिवासियों को ज़मीन, रोज़गार, मुआवज़ा, अधिकार के बारे में मालूम नहीं?



चित्र 3 - ATEPL में ज़मीन का बंटवारा

कोयला – सालाना 1.33 करोड़ टन की ज़रूरत पड़ेगी. हर दो घंटे में 40 डब्बों को भर कर एक रेलगाड़ी कोयला. 180 कि.मी. लम्बी नयी रेल पटरी बिछानी पड़ेगी. जो अंबिकापुर-बिजुरी लाइन से जुड़ेगी जिस पर पहले से ही कोयले से लदी हुयी गाड़ियों की भीड़ है. अगर EIA नहीं बताती है कि यह कैसे सम्भव है तो जनता खुद तथ्य इकठ्ठा कर सकती है. कितनी गाड़ियां चल रही हैं? कितनी दुर्घटनाएं हुई? धूल कैसे माप सकते हैं? प्राइवेट कम्पनी के मुनाफ़े के लिए सरकार करोड़ों का खर्च उठा सकती है, लेकिन पब्लिक सुविधा के लिए नहीं?

पानी – दिन में 15.3 करोड़ लीटर सोन नदी से, 60 कि.मी. लम्बी, 80 मी. ऊचाई लाँघती हुई पाइप से आएगी. नदी में इतना पानी होगा? नीचे नगरपालिका, TPP, पेपर मिल इत्यादि ग्राहक हैं जिनको पानी की आवश्यकता है. कच्चे पानी को साफ़ करना पड़ेगा. उसका कचरा कहाँ फेकेंगे? पानी का भाप बनने से 35 फीसदी उड़ जायेगा. लोहे के साथ ज़हरीले धातु (क्रोमियम, निकल, वनैडियम इत्यादि) मिला कर टरबाइन बनता है. टरबाइन घिसेगा तो ये धातु पानी में मिल जायेंगे. EIA में इन सारे नुकसानों की भरपाई का हिसाब होना चाहिए.

<u>अब आते हैं उन चीज़ों तक जो ATEPL से **बाहर** आएंगी</u>:

ऊर्जा – पहले दो टरबाइन लगने थे जिनकी क्षमता 1,320 मेगावाट (MW) थी. अब चार टरबाइन और 3,200 MW का प्रस्ताव है. DPR कहता है कि सब के विकास के लिए अधिक बिजली ज़रूरी है; कोयला जला कर पैदा

करना सबसे बेहतर. लेकिन (1) राष्ट्रिय मौसमी बदलाव योजना ने माना है कि ऊर्जा कोयले से नहीं, 'साफ़' साधनों से पैदा होगा; (2) TPP अधिक कामयाब है लेकिन उसका खर्च ज़्यादा है; (3) *सब* के विकास के लिए ज़रूरी नहीं कि अधिक बिजली बने, परन्तु *सब* को समान बिजली मिले. EIA में इन तीनों की व्याख्या होनी चाहिए.

रोज़गार – निर्माण के समय प्लांट में 350 पक्की और 250 कच्ची नौकिरयां; और चलाने के समय 550 पक्की और 50 कच्ची नौकरियां लगेंगी. यानि, एक रोज़गार पर औसत रु.6 करोड़ लगेगा. यह भी दावा है कि प्लांट के आसपास अन्य छोटी फैक्ट्रियां और व्यवसाय पैदा होंगे. लेकिन बगल के सिंगरौली ज़िले में, जहाँ चार बड़े TPP खुल चुके हैं, वहां 2020 में 6,582 युवाओं ने रोज़गार के लिए फॉर्म भरा था. केवल 218 को नौकरी मिली. औसत कमाई थी रु.14,000 प्रति माह. क्या अनूपपुर ज़िले में भी विकास की यह कहानी दोहराएगी?

राख़ – कोयला जलने से एक-तिहाई राख में बदल जाता है. मोटा हिस्सा भट्टी के नीचे गिरता है (*बॉटम* ऐश); महीन हिस्सा चिमनी से ऊपर उड़ता है (*फ्लाई* ऐश). बॉटम ऐश को पानी के साथ मिला कर ऐश पोंड भेज देंगे; फ्लाई ऐश को चिमनी में ESP द्वारा नीचे गिरा कर गोदामों में जमा कर देंगे. बाद में दोनों का उपयोग इस्पात, सीमेंट, सड़क, इत्यादि में होगा. लेकिन जो सबसे महीन हिस्सा है वो ऊंची चिमनी से सैंकड़ों किलोमीटर फैलेगा. कोयले में जो ज़हर होते हैं (पारा, निकल, कैडमियम जैसे धातु; गंधक, नाइट्रोजन, फ़्लोरिन जैसे गैस), राख़ के साथ साथ फैलेंगे. इंसान, पशु पक्षी मछली, पेड़ पौधे फल, सभी प्रभावित होंगे. इन सबका वर्णन EIA में होगा?

अन्य – किसी भी TPP में केमिकल होंगे (चूना, हाइड्रोजन, तेल, पेंट, इत्यादि). कोयले और मिट्टी का धूल होगा. शोर और काम का दबाव होगा. दुर्घटनाएं, खास तौर से कच्ची नौकरी और दिहाड़ी के लिए, आम होंगी. ATEPL केवई नदी के तट पर स्थित है, इसलिए सारा मल केवई में जायेगा. प्लांट पहाड़ी पर है, हवा उत्तर से बहती है, और दक्षिण में 100 किलोमीटर तक सोन घाटी फैली है. इसलिए घाटी में वायु प्रदूषण का पूरा इंतज़ाम है. इन सभी का फेफड़े, आँख, चमड़ी, नस, हड्डी, दिल, सेहत पर असर पेड़गा. EIA इन पर मौन रहेगा?

मोटी बात क्या है?

1. प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार है.
2. लेकिन EIA (पर्यावरणीय असर का आंकलन) अभी पब्लिक नहीं है.
3. EIA बनाने वाले को पैसा कम्पनी देती है, इसलिए पक्ष उसी का होता है.
4. लोग पहले से सावधान हो सकते हैं कि EIA में क्या होना चाहिए.
5. और अगर चाह हो, तो जनता अपने पक्ष का EIA खुद तैयार कर सकती है.

ऊपर दिए हुए तरीकों को समझ कर:

उड़ीशा के भुवनेस्वर में बस्ती वासियों ने वायु प्रदूषण को नाप लिया है.
तमिलनाडु के कोडाइकनाल में विद्यार्थियों और मज़दूरों ने पानी में पारा नापा है.
राजस्थान में पिंडवाड़ा के पत्थर कारीगरों ने अपनी बीमारी के जड़ को खोज निकाला है.
उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के किसानों के हिसाब से फेफड़ों के रोग की कीमत रु.42,000 करोड़ है.

वे कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते?

दुनू राय
खतरा केंद्र
अगस्त 2025